RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 4 से 10 अप्रैल 2026 भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित वर्ष- 13 अंक-86 पृष्ठ- 8 मूल्य- रु. 5 /-

मार्च में GST संग्रह 8.2% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पहुंचा

टैक्स कलेक्शन में लगातार मजबूती, आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत; पूरे वित्त वर्ष में GST राजस्व 18.4% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली: मार्च 2026 में भारत का माल और सेवा कर (GST) संग्रह 8.2 प्रतिशत बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ हो गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा पिछले साल के मार्च महीने के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन दर्शाता है।

मार्च में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से प्राप्त GST राजस्व में 9.1% की वृद्धि हुई, जबकि आयात से प्राप्त राजस्व में 6.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मजबूत आंकड़ा अर्थव्यवस्था में सुधार, खपत बढ़ने और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देता है।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के दौरान कुल GST संग्रह 18.4% बढ़कर ₹22.08 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ₹3.43 लाख करोड़ अधिक है। यह आंकड़ा सरकार की आर्थिक सुधारों, बेहतर अनुपालन और डिजिटल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, GST संग्रह में निरंतर वृद्धि आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और कर प्रणाली में सुधार को दर्शाती है। हमारा फोकस अब और बेहतर अनुपालन, सरलीकरण और छोटे व्यापारियों को राहत देने पर रहेगा।

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च का मजबूत आंकड़ा त्योहारी सीजन के बाद की मांग में सुधार और बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम का नतीजा है। हालांकि, कुछ राज्यों में अभी भी इंपोर्टेड गुड्स पर निर्भरता अधिक होने के कारण राजस्व वृद्धि में असमानता बनी हुई है।

सरकार अब GST संग्रह को और बढ़ाने के लिए ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल और AI आधारित एनालिटिक्स को और मजबूत करने की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो FY27 में GST कलेक्शन ₹24 लाख करोड़ के पार जा सकता है।

क्रेडिटर्स की समिति रियल्टी दिवालियापन मामलों में भूमि प्राधिकरणों को आमंत्रित कर सकेगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के दिवालिया होने पर अब तेज और पारदर्शी समाधान संभव; होमबायर्स और क्रेडिटर्स दोनों को फायदा, NCLT प्रक्रिया में नया मोड़

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र के दिवालियापन मामलों में क्रेडिटर्स की समिति (Committee of Creditors - CoC) अब भूमि प्राधिकरणों, डेवलपमेंट अथॉरिटीज और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी। यह फैसला रियल्टी प्रोजेक्ट्स के दिवालिया होने पर होमबायर्स के हितों की बेहतर सुरक्षा और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित दिवालियापन मामलों में अक्सर भूमि संबंधी जटिलताएं आती हैं। अब CoC को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह संबंधित भूमि प्राधिकरणों को सीधे आमंत्रित कर सके। इससे परियोजना की मंजूरी, लैंड टाइटल और अन्य मुद्दों पर तेजी से फैसला लिया जा सकेगा।

यह बदलाव दिवालिया और दिवालियापन संहिता (IBC) में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा है। वर्तमान में कई रियल्टी प्रोजेक्ट्स वर्षों से NCLT में फंसे हुए हैं, जिससे लाखों होमबायर्स प्रभावित हैं। नए प्रावधान से CoC को अधिक लचीलापन मिलेगा और परियोजनाओं को पूरा करने की प्रक्रिया सरल होगी।

उद्योग विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे फंसे प्रोजेक्ट्स को पुनरुद्धार मिल सकता है और नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने जोर दिया कि सरकार होमबायर्स के हितों की रक्षा करते हुए दिवालिया प्रक्रिया को अधिक कुशल और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बदलाव से NCLT में लंबित रियल्टी मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

रिस्क ऑफ! बैंक अब सिर्फ प्राइम कस्टमर्स को ही दे रहे लोन

बढ़ते एनपीए के डर से बैंकों ने रिटेल और एमएसएमई लोन में सतर्कता बरती, प्राइम कस्टमर्स पर फोकस; असुरक्षित लोन में भारी कमी

नई दिल्ली: बढ़ते ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) के कारण भारतीय बैंक अब ज्यादातर प्राइम कस्टमर्स (उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों) को ही लोन दे रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में बैंकों ने असुरक्षित रिटेल लोन, पर्सनल लोन और छोटे एमएसएमई लोन में सावधानी बरतना शुरू कर दिया है।

आरबीआई के आंकड़ों और बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक प्राइम और सुपर-प्राइम सेगमेंट (क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर) में लोन वितरण में 18% की वृद्धि हुई, जबकि सब-प्राइम और मीडियम रिस्क वाले ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन में 12-15% की कमी आई है। एक प्रमुख निजी बैंक के रिटेल बैंकिंग प्रमुख ने कहा, हम अब रिस्क को प्राथमिकता दे रहे हैं। अच्छे क्रेडिट स्कोर और स्थिर आय वाले ग्राहकों को ही आसानी से लोन मिल रहा है। बाकी मामलों में हम अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूख बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इससे छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है।

आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में बैंकों से आग्रह किया था कि वे रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करें, लेकिन क्रेडिट फ्लो को पूरी तरह रोकें नहीं। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले कुछ तिमाहियों में प्राइम लेंडिंग का ट्रेंड और मजबूत हो सकता है।

Maruti Suzuki March Sales Jump 16.7% to 2.25 Lakh Units; FY26 Volumes Cross 24.2 Lakh

Strong festive demand and rural recovery drive robust performance; Company maintains leadership with record annual sales

New Delhi: Maruti Suzuki India Ltd, the country's largest carmaker, reported a 16.7% year-on-year increase in domestic sales for March 2026, dispatching 2,25,000 units compared to 1,93,000 units in March 2025. This strong show helped the company cross the 24.2 lakh unit mark for the full financial year 2025-26.

The company sold 19,42,000 passenger vehicles in FY26, registering a healthy 12.8% growth over the previous year. Including commercial vehicles and exports, the total dispatches for the year stood at 24.2 lakh units.

Maruti Suzuki's Managing Director Hisashi Takeuchi attributed the robust March performance to improved rural sentiment, festive buying, and strong demand for its SUV and premium hatchback models. We are seeing healthy traction across segments, especially in SUVs where our models like Brezza, Grand Vitara, and Fronx continue to perform exceptionally well, he said.

The company's SUV portfolio contributed nearly 48% of total domestic sales in March, reflecting the ongoing shift in customer preference towards higher ground clearance vehicles. Maruti also witnessed steady growth in its Arena and Nexa dealership networks.

Analysts noted that Maruti Suzuki maintained its dominant market share of around 42% in the passenger vehicle segment despite increasing competition from Hyundai, Tata Motors, Mahindra, and Toyota. The company's aggressive expansion of production capacity at its Gujarat and Manesar plants has helped it meet the rising demand efficiently.

Looking ahead, Maruti Suzuki remains optimistic about FY27, expecting continued growth driven by new model launches, increasing rural incomes, and its foray into the electric vehicle segment with the upcoming eVX.

Maruti Suzuki shares close rose on BSE following the sales announcement, as investors cheered the company's consistent volume growth and strong execution.

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

The Rise of Domestic Investors: Is India Becoming a Self-Sustained Market?

For many years, the Indian stock market was heavily dependent on foreign investors. Whenever foreign institutional investors (FIIs) bought shares, the market went up. When they sold, markets fell sharply. But in the last few years, a big change has taken place. Indian investors themselves are now playing a powerful role. This has raised an important question: is India becoming a self-sustained market?

The answer seems increasingly positive. One of the biggest drivers of this change is the Systematic Investment Plan (SIP) culture. Every month, crores of Indians invest regularly in mutual funds through SIPs. Monthly SIP inflows have crossed ₹20,000 crore in recent years, showing strong retail participation. This steady flow of money provides stability to the market even when foreign investors pull out funds.

Earlier, when FIIs sold heavily, markets used to crash. But now, domestic institutional investors (DIIs), including mutual funds, insurance companies, and pension funds, step in to buy. This balancing effect reduces sharp volatility. During several recent global uncertainties whether due to war fears, rising US interest rates, or oil price spikes domestic investors have helped cushion the fall.

Another major reason behind this rise is increased financial awareness. With easy access to mobile trading apps, digital KYC, and online financial education, more young Indians are entering the stock market. Small-town participation has also grown significantly. Today, demat accounts in India have crossed 15 crores, which shows how rapidly equity culture is spreading.

Government reforms have also played a role. Initiatives like Make in India, infrastructure push, manufacturing growth, and digital economy expansion have increased confidence in India's long-term growth story. As people see economic progress around them, they feel more comfortable investing in Indian companies.

At the same time, India's economy has shown resilience compared to many global economies. While some developed countries faced slow growth and recession fears, India continued to grow steadily. This has strengthened the belief that long-term investment in Indian equities can create wealth.

However, it is important to understand that India is not completely independent of foreign money yet. FIIs still influence short-term market movements. Large global events like US elections, geopolitical tensions, or changes in Federal Reserve interest rates can affect capital flows into emerging markets like India.

But the difference today is that India is no longer fully dependent. Domestic investors now provide a strong foundation. The regular monthly inflow through SIPs acts like a support system for the market.

In simple terms, earlier the Indian market was like a house supported by one main pillar foreign investors. Now, it stands on two strong pillars foreign and domestic investors. And the domestic pillar is becoming stronger every year.

For common investors, this is good news. A market driven by its own people is generally more stable and less vulnerable to sudden global shocks. It reflects confidence in the country's future.

India's growing middle class, rising incomes, and increasing financial literacy suggest that domestic participation will continue to grow. If this trend continues, India may truly become a self-sustained equity market in the coming years powered not just by global capital, but by the savings and confidence of its own citizens.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

कोल इंडिया की बिक्री छह महीने बाद पहली बार बढ़ी: गैस संकट और गर्मी की मांग से उछाल

बिजली उत्पादन में कोयले की बढ़ती जरूरत से कोल इंडिया को राहत, दिसंबर में बिक्री 8.2% बढ़कर 57.4 मिलियन टन पहुंची; FY26 में रिकवरी की उम्मीद

नई दिल्ली: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की बिक्री छह महीने बाद पहली बार बढ़ी है। दिसंबर 2025 में कंपनी की कोयला बिक्री 8.2 प्रतिशत बढ़कर 57.4 मिलियन टन हो गई, जबकि पिछले साल दिसंबर में यह 53.05 मिलियन टन थी। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण गैस की कमी और आगामी गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग है। कई गैस आधारित बिजली संयंत्रों में गैस की अनुपलब्धता के कारण बिजली कंपनियां कोयला आधारित प्लांट्स की ओर रुख कर रही हैं। इससे कोल इंडिया की डिस्पैच में सुधार हुआ है।

कोल इंडिया के चेयरमैन पी.एम. प्रसाद ने कहा, दिसंबर में हमने मजबूत प्रदर्शन किया है। गैस संकट और बढ़ती बिजली मांग ने कोयले की खपत बढ़ाई है। हम उत्पादन बढ़ाने और रेलवे के साथ समन्वय बनाए रखने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।" विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी से अप्रैल तक बिजली की पीक डिमांड बढ़ने के कारण कोल इंडिया की बिक्री में और सुधार हो सकता है। कंपनी ने दिसंबर में 70.8 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो पिछले साल से 6.1% अधिक है।

हालांकि, कंपनी को अभी भी लॉजिस्टिक्स चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की रेक उपलब्धता और सड़क परिवहन की सीमाएं उत्पादन बढ़ाने में बाधक बनी हुई हैं। कोल इंडिया ने इन मुद्दों को दूर करने के लिए रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ समन्वय बढ़ाया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में कोल इंडिया की कुल बिक्री 4.8% घटकर 4.92 अरब टन रह गई थी। लेकिन दिसंबर में आई बढ़ोतरी से उम्मीद जगी है कि पूरे वर्ष में कंपनी लक्ष्य के करीब पहुंच सकती है।

HMSI Logs 29% Rise in Sales at 5,49,145 Units in March

Strong demand for Activa, Shine, and premium motorcycles drives robust performance; Honda aims to strengthen its position in the fast-growing Indian two-wheeler market

Bhopal: Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI) reported a strong 29% year-on-year increase in total sales for March 2026, dispatching 5,49,145 units compared to 4,25,000 units in March 2025.

The company's scooter segment continued to dominate, led by the evergreen Activa, which remained the highest-selling two-wheeler model in the country. The motorcycle segment also showed healthy growth, driven by models like Shine, Unicorn, and the premium Hornet and CB200X series.

HMSI's cumulative sales for FY26 stood at 58.2 lakh units, marking a 14% growth over the previous financial year. The company maintained its position as the second-largest two-wheeler manufacturer in India.

HMSI President & CEO Minoru Kato said, "March has been an excellent month for us. Strong rural recovery, festive buying, and positive consumer sentiment have driven demand across both scooter and motorcycle segments. Our focus on product quality, technology, and expanding our dealer network has yielded good results."

The company has been aggressively expanding its manufacturing footprint. Its fourth plant in Gujarat is now operating at optimal capacity, supporting the growing demand for both domestic and export markets.

Industry analysts noted that HMSI's consistent double-digit growth reflects its successful strategy of balancing mass-market products with premium offerings. The company is also preparing to launch new electric scooter models in the coming months to strengthen its presence in the rapidly growing EV two-wheeler segment.

With the Indian two-wheeler industry expected to grow steadily in FY27, driven by rising rural incomes and increasing demand for personal mobility, HMSI is well-positioned to capitalize on the opportunity. The company aims to achieve 65 lakh unit sales in the next financial year.

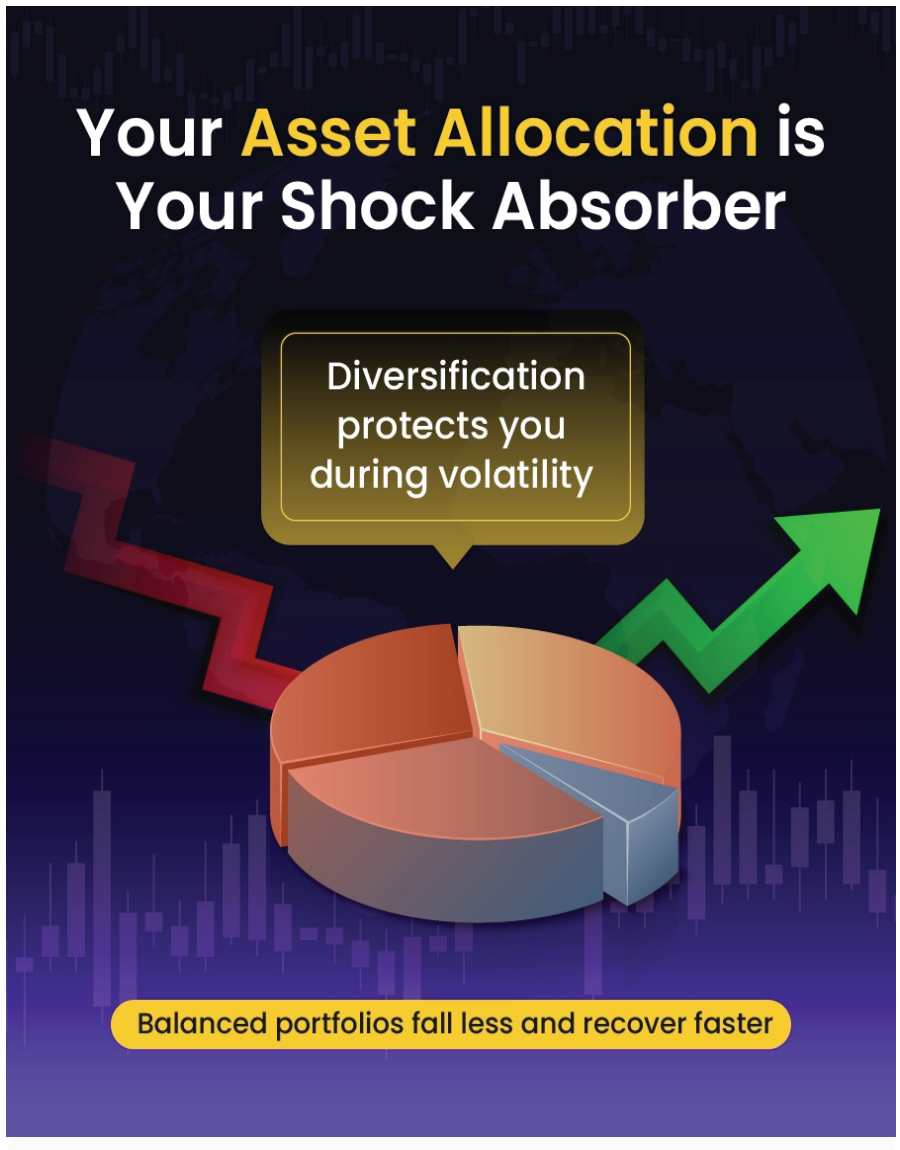

Vision Invest Tech Private Limited
ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor
(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com

Vision Invest Tech Private Limited
ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor
(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com

Inox Clean Energy Completes ₹5,000 Crore Acquisition of Vibrant Energy

Deal significantly boosts Inox's renewable portfolio to over 5 GW; Marks one of the largest transactions in India's clean energy space

Mumbai: Inox Clean Energy, the renewable energy arm of the Inox Group, has successfully completed the acquisition of Vibrant Energy for an enterprise value of ₹5,000 crore. The deal, one of the largest in India's renewable energy sector in recent times, significantly strengthens Inox's position as a major player in the country's green energy transition.

Vibrant Energy, backed by global investors, has a portfolio of over 2.8 GW of renewable assets, primarily comprising solar and wind projects across Rajasthan, Gujarat, Karnataka, and Tamil Nadu. With this acquisition, Inox Clean Energy's total renewable capacity will cross 5 GW, making it one of the top renewable energy companies in India.

Inox Group Chairman Pavan Jain described the acquisition as a transformational move" that aligns with the group's long-term vision of becoming a leading clean energy solutions provider. This acquisition not only adds substantial operational capacity but also brings in a strong pipeline of projects under development," he said.

The deal is expected to be funded through a mix of internal accruals, debt, and equity. Inox Clean Energy has already secured commitments from leading domestic and international banks for the transaction.

Industry analysts have welcomed the development, noting that the acquisition comes at a time when India is aggressively pushing towards its 500 GW non-fossil fuel capacity target by 2030. The combined entity will benefit from economies of scale, improved bargaining power with equipment suppliers, and better access to capital.

The transaction also reflects growing consolidation in the renewable energy sector, as larger players look to acquire operational assets to accelerate growth and meet aggressive renewable purchase obligations set by states.

With this deal, Inox Clean Energy has sent a strong signal of its intent to play a bigger role in India's clean energy story in the coming years.

Texmaco Rail Bags ₹357 Crore Order from JSW Group for 20 Freight Wagon Rakes

Major contract strengthens Texmaco's position in India's growing freight wagon segment; Order book swells amid rising demand for rail logistics

New Delhi: Texmaco Rail & Engineering Ltd has secured a significant order worth ₹357 crore from the JSW Group for the supply of 20 freight wagon rakes. The Letter of Intent (LOI) was issued by JSW Steel and JSW Infrastructure for specialised freight wagons to be used in their captive logistics operations.

The order includes the design, manufacturing, and supply of high-capacity BOXNHL and BCNHL type wagons, which are widely used for transporting coal, iron ore, and other bulk commodities. Delivery is scheduled to commence from the third quarter of FY27 and will be completed within 12 months.

Texmaco Rail's Managing Director S. K. Poddar described the order as a "testament to the company's technical expertise and manufacturing excellence." He added that the company is witnessing strong demand from both public and private sectors as Indian Railways and private players expand their rolling stock to meet the growing freight transportation needs of the economy

This is the second major order Texmaco has received from the JSW Group in the last 18 months, reflecting a deepening relationship between the two companies. The latest contract will further .

strengthen Texmaco's already robust order book, which now stands at over ₹4,800 crore.

Industry analysts view the order positively, noting that India's freight wagon requirement is expected to grow significantly in the coming years due to dedicated freight corridors, increased coal movement, and the expansion of private rail operators. Texmaco Rail, with its modern manufacturing facilities in Raipur and Belgharia, is well-positioned to capitalise on this opportunity.

JSW Steel Announces ₹7,875 Crore Investment by Japan's JFE in JSW Kalinga; Acquires 25% Stake

Landmark partnership to boost JSW's downstream steel capacity and technological edge; Deal marks one of the largest Japanese investments in Indian steel sector

Kalinga: JSW Steel Ltd has signed a major strategic partnership with Japan's JFE Steel Corporation, under which the Japanese steel major will invest ₹7,875 crore to acquire a 25% stake in JSW Kalinga Ltd, a wholly-owned subsidiary of JSW Steel.

The investment will be used to set up a state-of-the-art 2.5 million tonnes per annum (MTPA) downstream steel plant in Kalinganagar, Odisha. The facility will focus on producing high-grade automotive steel, electrical steel, and other value-added flat products using advanced Japanese technology.

JSW Steel Chairman Sajjan Jindal described the partnership as a "significant milestone" in the company's journey towards becoming a global leader in high-end steel manufacturing. "JFE brings world-class technology and decades of expertise in advanced steelmaking. This collaboration will help us serve the fast-growing Indian automotive and electrical sectors with superior quality products," he said.

JFE Steel President & CEO Yoshihisa Kitano stated that India is a strategically important market for the company. "We are excited to partner with JSW, which shares our commitment to innovation, sustainability, and quality. This investment reinforces our long-term commitment to the Indian market," he added.

The deal is subject to regulatory approvals and is expected to be completed in the next 6–9 months. Upon completion, JSW Kalinga will become a joint venture between JSW Steel and JFE Steel.

Analysts welcomed the development, noting that the partnership will significantly enhance JSW Steel's technological capabilities and product portfolio while strengthening its position in the premium steel segment.

RBL Bank Receives RBI Nod for Emirates NBD Stake Acquisition; Sebi Approval Still Pending

UAE-based bank to acquire up to 9.99% stake in RBL Bank; Deal to bring strategic capital and international expertise to the private lender

Mumbai: RBL Bank has received approval from the Reserve Bank of India (RBI) for Emirates NBD Bank PJSC's proposed acquisition of up to 9.99% stake in the private sector lender. The development marks a significant step forward in the landmark partnership between the two banks.

Emirates NBD, one of the largest banking groups in the Middle East, plans to invest approximately ₹2,000 crore in RBL Bank through a mix of fresh equity issuance and secondary market purchase. The deal, if completed, will make Emirates NBD the single largest shareholder in RBL Bank.

RBL Bank's Managing Director & CEO R. Subramania said, we are delighted to receive RBI approval for this strategic partnership. Emirates NBD brings global best practices, strong risk management capabilities, and deep expertise in retail and wholesale banking. This investment will strengthen our capital position and accelerate our growth journey.

The RBI nod is a key regulatory milestone. However, the transaction still requires approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other relevant authorities. Both banks expect to complete the remaining formalities in the coming weeks.

Industry analysts have welcomed the development, noting that the entry of a strong foreign institutional investor will enhance RBL Bank's credibility and provide it with access to international markets and best-in-class technology. The deal is also seen as a positive signal for foreign investment in India's banking sector.

Once completed, the transaction will be one of the largest foreign investments in an Indian private bank in recent years and is expected to support RBL Bank's ambitions in retail lending, digital banking, and wealth management.

सुजलॉन को गेल से मिला 100 MW का विंड प्रोजेक्ट, छठी बार दोहराया ऑर्डर

गेल के साथ मजबूत साझेदारी जारी, सुजलॉन की ऑर्डर बुक और मजबूत; नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की स्थिति सुदृढ़

नई दिल्ली: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को गेल (इंडिया) लिमिटेड से 100 मेगावॉट के विंड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। यह गेल से सुजलॉन को मिला छठा दोहराया ऑर्डर (repeat order) है, जो दोनों कंपनियों के बीच लंबे समय से चली आ रही मजबूत साझेदारी को दर्शाता है।

इस प्रोजेक्ट के तहत सुजलॉन गुजरात और राजस्थान में विंड टरबाइन जनरेटर (WTG) की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करेगी। प्रोजेक्ट को 2027 की पहली तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑर्डर की कुल वैल्यू करीब 650-700 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सुजलॉन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जयदेव मिस्त्री ने कहा, "गेल से लगातार छठी बार ऑर्डर मिलना हमारी तकनीकी क्षमता, प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन और आफ्टर-सेल्स सर्विस पर उनके भरोसे को दिखाता है। यह ऑर्डर हमारी ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा।"

सुजलॉन के पास वर्तमान में कुल 4.2 गीगावॉट का ऑर्डर बुक है, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ऑर्डर शामिल हैं। कंपनी ने हाल के वर्षों में वित्तीय स्थिति सुधारने, कर्ज कम करने और नई तकनीकी रूप से उन्नत 3.X MW और 4.X MW टरबाइनों को बाजार में लाने पर जोर दिया है।

गेल के चेयरमैन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट कंपनी के नेट-जीरो लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गेल पहले से ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय है और अब विंड एनर्जी में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऑर्डर से सुजलॉन की स्थिति और मजबूत होगी। भारत सरकार के 500 गीगावॉट नॉन-फॉसिल ऊर्जा लक्ष्य को देखते हुए विंड सेक्टर में अगले कुछ वर्षों में भारी निवेश आने की उम्मीद है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने FY26 में 5 गीगावॉट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी

सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में रिकॉर्ड विस्तार, कंपनी की कुल क्षमता 12.5 गीगावॉट के पार; 2030 तक 45 गीगावॉट का लक्ष्य मजबूत

नई दिल्ली: अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने वित्त वर्ष 2026 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस वित्त वर्ष में 5 गीगावॉट (GW) से अधिक नई सोलर और विंड क्षमता जोड़कर कुल स्थापित क्षमता को 12.5 गीगावॉट के पार पहुंचा दिया है।

यह उपलब्धि अदाणी ग्रीन के लिए एक नया रिकॉर्ड है। कंपनी ने मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में बड़े सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स पूरा किए। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स हाइब्रिड (सोलर + विंड) और फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) प्रकृति के हैं, जो बिजली की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

अदाणी ग्रीन एनर्जी के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, FY26 हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। 5 गीगावॉट से अधिक क्षमता जोड़ना हमारे 'ग्रोथ विद गवर्नेंस' के सिद्धांत को दर्शाता है। हम 2030 तक 45 गीगावॉट की क्षमता हासिल करने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

कंपनी ने इस वित्त वर्ष में कई बड़े पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) भी साइन किए हैं। इनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहक शामिल हैं। अदाणी ग्रीन की मजबूत बैलेंस शीट और कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अदाणी ग्रीन का यह विस्तार भारत के 500 गीगावॉट नॉन-फॉसिल ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कंपनी की यह उपलब्धि निजी क्षेत्र द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में किए जा रहे भारी निवेश को भी रेखांकित करती है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर बाजार में इस खबर के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली।

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.
- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.
EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	22713	23533	23158	22935	22560	22337	21962	21739
BANK NIFTY	51549	54239	52984	52267	51012	50295	49040	48323
SENSEX	73134	76332	75149	74141	72958	71950	70767	69759
FINNIFTY	24042	25063	24592	24317	23846	23571	23100	22825
MIDCAP	12395	12907	12666	12530	12289	12153	11912	11776
ACC	1325	1434	1383	1354	1303	1274	1223	1194
AXISBANK	1198	1277	1243	1220	1186	1163	1129	1106
ABCAPITAL	298	330	319	309	298	288	277	267
BHARTIARTL	1792	1907	1866	1829	1788	1751	1710	1673
BHEL	248	272	265	256	249	240	233	224
BIOCON	352	399	385	369	355	339	325	309
BEL	422	466	448	435	417	404	386	373
CDSL	1184	1295	1245	1215	1165	1135	1085	1055
DATAPATTERN	3088	3567	3396	3242	3071	2917	2746	2592
ESCORTS	2841	3034	2943	2892	2801	2750	2659	2608
EICHERMOTOR	6660	7164	7028	6844	6708	6524	6388	6204
FEDERAL BANK	266	286	278	272	264	258	250	244
GRINFRAPOJECT	848	937	894	871	828	805	762	739
HDFCBANK	752	792	774	763	745	734	716	705
HCLTECH	1394	1501	1457	1425	1381	1349	1305	1273
HINDUNILVR	2065	2213	2166	2116	2069	2019	1972	1922
HAL	3680	3980	3839	3760	3619	3540	3399	3320
HYUNDAI	1707	1972	1900	1804	1732	1636	1564	1468
IOC	135	150	145	140	135	130	125	120
ICICIBANK	1216	1283	1259	1237	1213	1191	1167	1145
INFY	1298	1383	1344	1321	1282	1259	1220	1197
ITC	292	302	298	295	291	288	284	281
KOTAKBNK	358	385	375	366	356	347	337	328
LICHOUSING	516	553	536	526	509	499	482	472
LT	3610	3918	3801	3705	3588	3492	3375	3279
LUPIN	2265	2550	2455	2360	2265	2170	2075	1980
MARUTI	12570	13612	13256	12913	12557	12214	11858	11515
M&M	3007	3233	3156	3082	3005	2931	2854	2780
MGL	952	1011	985	969	943	927	901	885
MAZGAONDOC	2263	2673	2508	2386	2221	2099	1934	1812
PFC	402	457	431	416	390	375	349	334
RECLTD	325	355	340	333	318	311	296	289
RELIANCE	1351	1437	1410	1381	1354	1325	1298	1269
SBIN	1017	1095	1063	1040	1008	985	953	930
SUNPHARMA	1692	1923	1857	1774	1708	1625	1559	1476
SHRIRAMFINANCE	891	985	956	923	894	861	832	799
TITAN	4078	4347	4227	4153	4033	3959	3839	3765
TCS	2446	2623	2547	2497	2421	2371	2295	2245
TATAMOTORS	303	327	318	311	302	295	286	279
UPL	591	644	623	607	586	570	549	533
VALIENT	232	282	259	246	223	210	187	174
WIPRO	195	207	201	198	192	189	183	180

जी एंटरटेनमेंट ने 215 मिलियन डॉलर के FCCB रद्द किए, बॉन्डधारकों ने भू-राजनीतिक तनाव के बीच एग्जिट मांगा

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स को समय से पहले समाप्त करने का फैसला, कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ा; शेयर बाजार में गिरावट

मुंबई: जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने 215 मिलियन डॉलर (लगभग 1,800 करोड़ रुपये) के फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) को रद्द करने का फैसला लिया है। कंपनी ने कहा कि बॉन्डधारकों ने भू-राजनीतिक तनाव और बाजार की अनिश्चितता के कारण समय से पहले एग्जिट की मांग की थी, जिसके बाद बोर्ड ने यह कदम उठाया।

जी एंटरटेनमेंट ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि बॉन्डधारकों ने हाल के वैश्विक घटनाक्रमों (ईरान-इजराइल संघर्ष और डॉलर की मजबूती) को देखते हुए अपने निवेश को वापस लेने की इच्छा जताई। कंपनी ने कहा कि FCCBs को समय से पहले रिडीम करने से उसके बैलेंस शीट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, लेकिन यह कदम निवेशकों के हित में उठाया गया है।

कंपनी के सीएफओ ने कहा, वर्तमान अनिश्चित माहौल में हमने बॉन्डधारकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। हम अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत रखते हुए सभी दायित्वों को समय पर पूरा करेंगे।

यह FCCBs मूल रूप से 2024 में जारी किए गए थे और 2029 में परिपक्व होने थे। इनका कन्वर्शन प्राइस काफी ऊंचा था, जिसके कारण बॉन्डधारक इक्विटी में कन्वर्ट होने के बजाय कैश एग्जिट चाहते थे।

विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना जी एंटरटेनमेंट के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। कंपनी पहले से ही सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन राजस्व में मंदी का सामना कर रही है। FCCBs को समय से पहले रिडीम करने से उसके शॉर्ट-टर्म कैश फ्लो पर दबाव बढ़ सकता है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी को अब नए फंडिंग विकल्प तलाशने होंगे या अपनी गैर-कोर एसेट्स को बेचने पर विचार करना होगा।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in